भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1922

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

फिरोजपुर फीडर नहर पुनर्वासन और रीलाइनिंग परियोजना

1922. श्रीमती संजना जाटवः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पंजाब और राजस्थान में सिंचाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली "फिरोजपुर फीडर नहर पुनर्वासन और रीलाइनिंग" परियोजना के प्रस्ताव की केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा तकनीकी रूप से जांच की गई है और इसे 2.02 के लाभ-लागत अनुपात के साथ 2024 के मूल्य स्तर पर 647.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर व्यवहार्य पाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो डिज़ाइन पैरामीटर, वैधानिक अनुमोदन, संबंधित राज्यों के बीच लागत-साझेदारी व्यवस्था और परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य मानने के समग्र औचित्य सहित सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए तकनीकी-आर्थिक आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जी, हां।

(ख) और (ग): राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों की जांच केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए उनके दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है। यह जांच केंद्रीय जल आयोग के साथ-साथ केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सीएसएमआरएस), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) आदि जैसी अन्य केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करते हुए बहु-विषयक मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से की जाती है।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, "फिरोजपुर फीडर कैनाल रीहैबलीटेशन एंड रिलाइनिंग" परियोजना के डिजाइन पहलुओं का मूल्यांकन केंद्रीय जल आयोग में नहीं किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार के केंद्रीय अभिकल्प संगठन (सीडीओ) की मंज़ूरी निर्धारित प्रोफ़ार्मा में प्रस्तुत की गई थी।

फिरोजपुर फीडर कैनाल सिस्टम एक मौजूदा और कार्यात्मक सिंचाई प्रणाली है जबकि प्रस्तावित कार्य मौजूदा अवसंरचना के पुनर्वास और रिलाइनिंग तक ही सीमित है और इसमें कोई अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं है; विद्यमान कानूनों और नियमों के अनुसार वैधानिक मंजूरी लागू होती है।

परियोजना के लिए लाभ-लागत अनुपात का आकलन पैदावार और उपज की दरों, बीज, खाद और मज़दूरी आदि पर होने वाले व्यय जैसे इनपुट के आधार पर किया गया है, जिसे राज्य कृषि विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और इसका आकलन 2.02 लगाया गया है।

जैसा कि परियोजना प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, परियोजना लागत साझेदारी को अंतर-राज्यीय पहलुओं के अनुसार दो भागों में निर्धारित किया गया है:

भाग क: आरडी 0-55413 से	-	62.50% (पंजाब) : 37.50% (राजस्थान)
भाग ख: आरडी 55413-168230 से	-	54.13% (पंजाब) : 45.87% (राजस्थान)

इस संबंध में, राजस्थान सरकार ने पंजाब को अनुमोदित डीपीआर की अंतिम धनराशि के अनुसार, मानदंडों के अनुरूप साझा लागत वहन करने की सहमति प्रदान की है।

*****